



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2008/ज्येष्ठ 13, 1930

No. 201]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2008/JYAISTHA 13, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2008

सं. 26 (आर ई-2008)/2004-2009

फा. सं. 01/36/218/26/एम. 09/पीसी-5/ईपीसी जी-1, विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर ई-2008) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. पैराग्राफ 5.11.3 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को जोड़कर पैराग्राफ 5.11.4 पढ़ा जाएगा :—

“जब किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसे निर्यात उत्पादों पर रोक लगाने से पूर्व पहले से जारी ई पी सी जो प्राधिकार पत्रों के संबंध में निर्यात दायित्व की अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के रोक की अवधि के बराबर स्वतः ही बढ़ जाएगी और निर्यातक को रोक की अवधि के लिए औसत निर्यात दायित्व को भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी”।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd June, 2008

No. 26 (RE-2008)/2004-2009

F. No. 01/36/218/26/AM 09/PC-V/EPCG. 1.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Hand Book of Procedures, Vol. I (RE-2008) :

- 1 The following paragraph stands added after paragraph 5.11.3 to read as paragraph 5.11.4, as under :—

“Whenever a ban/restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of EPCG authorizations already issued prior to imposition of ban of such export products, would stand automatically extended for a period equivalent to the duration of ban, without any composition fee and exporter would not be required to fulfil average E.O. as well for the ban period”.

This issues in Public Interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign
Trade & ex-officio Addl. Secy.